

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद-1
संख्या: बारह-29-2008, दिनांक: दिसम्बर 18, 2008

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश ।

विषय: वेतन समिति-2008 की संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिये गये
निर्णय के अनुसार मकान किराया भत्ता/नगर प्रतिकर
भत्ता एवं स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रोत्साहन हेतु
निर्गत संशोधित दरें ।

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: जी-1-953/ दस-2008-
203/99, दिनांक 8-12-2008, जी-1-954/दस-2008-203/99, दिनांक
8-12-2008 व जी-2-1985/दस-2008-339/2008^{7.0.11-12-2008} की प्रतिलिपियाँ आपके
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जाती हैं। कृपया
उल्लिखित शासनादेशों में निहित निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित
करने का कष्ट करें ।

संलग्नक: यथोपरि ।

(अशोक कुमार)

अपर पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय,
नि० पुलिस उप महानिरीक्षक, मुख्यालय,
उत्तर प्रदेश ।

संख्या तथा दिनांक वही

21/12/08

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, इलाहाबाद ।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक, भवन/कल्याण, इलाहाबाद ।
- 3- पुलिस महानिरीक्षक, प्रो० एवं बजट, इलाहाबाद ।
- 4- पुलिस उप महानिरीक्षक, मुख्यालय, इलाहाबाद ।
- 5- पुलिस उप महानिरीक्षक, स्थापना, इलाहाबाद ।
- 6- वित्त नियंत्रक, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।
- 6- पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय/स्थापना, इलाहाबाद ।
- 7- अपर पुलिस अधीक्षक, स्थापना/मुख्यालय, इलाहाबाद ।
- 8- पुलिस उपाधीक्षक, स्थापना/मुख्यालय/भवन एवं कल्याण/विधि
प्रकोष्ठ, इलाहाबाद ।
- 9- मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी, मुख्यालय, इलाहाबाद ।
- 10- समस्त कार्यालय अधीक्षक/अनुभाग अधिकारी, पुलिस मुख्यालय,
इलाहाबाद ।



प्रेषक,

अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उत्प्र शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयअध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक: 08 दिसम्बर, 2008

विषय: वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिए गए शासन के निर्णय के अनुसार मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण हेतु गठित वेतन समिति-2008 के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों को कतिपय संशोधनों के साथ शासकीय सकल्प संख्या-वे0आ0-2-1313/दस-2008-59(एम)/2008 दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

2- वेतन समिति-2008 के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरूप प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को निम्नतालिका के अनुसार दिनांक 01 जनवरी, 2008 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के आधार पर उनके सम्मुख उल्लिखित दरों पर मकान किराया भत्ता अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्रम सं०	ग्रेड-वेतन/वेतनमान (रु०)	ग्रेड-ए की-1 तथा की-2 के नगरों में	ग्रेड-सी के नगरों में	अवर्गीकृत श्रेणी के क्षेत्र
1	2	3	4	5
1	1300	900	450	300
2	1400	930	465	310
3	1650	980	490	325
4	1800	1100	550	365
5	1900	1160	580	385
6	2000	1200	600	400
7	2400	1470	735	490
8	2800	1670	830	555
9	4200	2020	1010	670
10	4600	2760	1380	920
11	4800	2810	1405	935
12	5400	3150	1575	1050
13	6600	3780	1890	1260
14	7600	4480	2240	1490

अपर पुलिस महानिदेशक
ब० प्र० पुलिस मुख्यालय
इलाहाबाद।

16/12/08

दीपक कुमार
मुख्य सचिव
म० व० सेवा विभाग
43
16/12/08

15	8700	6910	3455	2300
16	8900	7280	3640	2430
17	10000	8200	4100	2730
18	12000	9200	4600	3000
19	वेतनमान 80000 निवृत्त	10500	5250	3500

श्रेणी ए, बी-1, बी-2, सी तथा अवर्गीकृत श्रेणी में आने वाले नगरों/क्षेत्रों से संबंधित तालिका

श्रेणी	नगर/क्षेत्र
ए, बी-1, बी-2	लखनऊ, कानपुर, मेरठ, बरेली, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, नोएडा क्षेत्र (गोतम बुद्ध नगर), मन्डिवाबाद, अलीगढ़ तथा मुरादाबाद के शहरी क्षेत्र।
सी	नजीबाबाद, नगीना, चोंदपुर, बिजनौर, चन्दीसी, सम्मल, अमरोहा, रामपुर, देवबन्द, सहारनपुर, रुड़की, शामली, कैराना, मुजफ्फर नगर, बड़ौत, भवानी, पिल्खुआ, हापुड़, मोदीनगर, खुर्जा, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर, हाथरस, मथुरा, सिकोहाबाद, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, सहस्रकान, बदौय, पीलीभीत, उन्नाव, शहजहाँपुर, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, शाहाबाद, गंगाघाट (जिला उन्नाव), रायबरेली, कन्नौज, उरई, फर्रुखाबाद-कम-फतेहगढ़, औरैया, इटावा, झाँसी, ललितपुर, मन्डोबा, बोंदा, फतेहपुर, बैसा, प्रतापगढ़, बहराइच, बलरामपुर, गीछा, नयाबगंज, टांडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, बस्ती, देवरिया, मठनाथगंजन, अजयगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद, गाजीपुर, भदोही, मुगलसराय, मिर्जापुर-कम-विधवाभवन, कन्नौज, खतोली, कीरतपुर, सोरकोट, हसनपुर, मुरादनगर, लोनी, बेहडा, हाजीपुर दादरी, जहाँगीराबाद, उज्जनी, बडेही, फरीदपुर, बिसनपुर, तिलहर, गोला गोकर्णनाथ, छिबरामऊ, जालौन, कोच, मधुसनीपुर, राठ, मुबारकपुर, ओबरा, रेनकुट के शहरी क्षेत्र।
अवर्गीकृत	उपर्युक्त श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य समस्त नगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र।

3- ग्रेड वेतन का तात्पर्य पूर्व वेतनमान के संबंध में पुनरीक्षित पे-बैंड में अनुमन्य संबंधित ग्रेड वेतन से है।

4- अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के संबंध में अलग से आदेश निर्यत किए जा रहे हैं।

5- ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों, जो उत्तर प्रदेश के बाहर नियुक्त हैं को मकान किराया भत्ता उसी दर पर अनुमन्य होगा जो उस नगर में नियुक्त भारत सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य है।

6- संशोधित मकान किराया भत्ता ऐसे समस्त पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जिन्हें सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है। यह भत्ता दोनों प्रकार के सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जो किराये के मकान में रहते हैं अथवा अपने निजी आवास में निवास करते हैं।

7- ऐसे राज्य कर्मचारियों, विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणोत्तर कर्मचारियों, जिनके द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने का विकल्प दिया गया हो अथवा मान लिया गया हो अथवा दिनांक 01 जनवरी, 2008 के पश्चात् सेवा में नियुक्त हुए हों, के मकान किराया भत्ता के संबंध में पूर्व में निर्गत आदेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

8- यह आदेश दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से लागू होंगे।

9- अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत प्रमादी रहेंगे।

भवदीय,

११/१२/०८

(अनूप मिश्र)

प्रमुख सचिव

संख्या जी-1-953(1)/दस-2008-205/99, तददिनांक

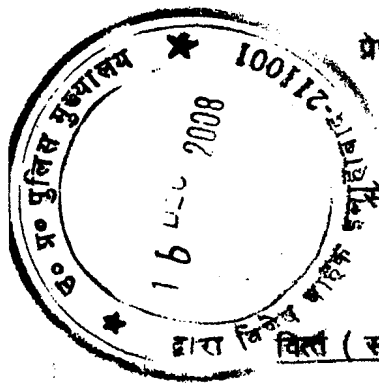
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- प्रमुख सचिव / सचिव, शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
- 1- महासंस्थाकार-1, 2 एवं 3, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
- 2- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 3- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2 (तीन-तीन प्रतियों में)
- 4- सचिव, श्री राज्यपाल।
- 5- विद्यान सभा/परिषद् सचिवालय।
- 6- निदेशक, किराया प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 7- समस्त कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(शिव प्रकाश)

विशेष सचिव।



प्रेषक.
 अनूप मिश्र,
 प्रमुख सचिव,
 उ०प्र० शासन।
 सेवा में,
 समस्त विभाग/प्रमुख कार्यालय/प्रमुख,
 उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-1

लखनऊ, दिनांक: 08 दिसम्बर, 2008

विषय: नगर प्रतिकर भत्ता की संशोधन दरें।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण हेतु गठित वेतन समिति-2008 के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों को कतिपय संशोधनों के साथ राजकीय संकल्प संख्या-वे०आ०-2-1313/दस-2008-69(एम)/2008, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

2- वेतन समिति-2008 के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरूप प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यू०जी०सी०, ए०आई०सी०टी०ई०, आई०सी०ए०आर० वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को निम्नतालिका के अनुसार दिनांक 01 जनवरी, 2008 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के अन्वय पर उनके सम्मुख उल्लिखित दरों पर नगर प्रतिकर भत्ता अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

ग्रेड वेतन(रूपया)	नगर प्रतिकर भत्ता की दरें (रूपया)			
	कानपुर, लखनऊ, नोयडा तथा ग्रेटर नोयडा क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र)	वासणसी, मेरठ, आगरा तथा इलाहाबाद (नगरीय क्षेत्र)	बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, तथा अलीगढ़ (नगरीय क्षेत्र)	शेख जिला मुख्यालय तथा अन्य नगर जिनकी आबादी* एक लाख या उससे अधिक है। (नगरीय क्षेत्र)
1	2	3	4	5
1300 से 1800 तक	170	120	80	60
1900 से 2800 तक	240	180	120	80
4200 से 4800 तक	360	270	180	120
5400 तथा इससे अधिक ग्रेड वेतन एवं उच्चतर वेतनमान	450	360	300	200

* वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर।

श्री पुलिस महानिदेशक
 पुलिस मुख्यालय
 इलाहाबाद।

16/12/08

श्री प्रमुख

श्री प्रमुख

18/12/08

2- ग्रेड वेतन का तात्पर्य पूर्व वेतनमान के संबंध में पुनरीक्षित पे-बैंड में अनुमन्य संबंधित ग्रेड वेतन से है।

3- ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को जो उत्तर प्रदेश के बाहर नियुक्त हैं, नगर प्रतिकर भत्ता उसी दर पर अनुमन्य होगा, जो उस नगर में नियुक्त भारत सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य है।

4- ऐसे राज्य कर्मचारियों, विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यूजी०सी०, ए०आई०सी०टी०ई०, आई०सी०ए०आर०) वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणरेतर कर्मचारियों, जिनके द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना घुनने का विकल्प दिया गया हो अथवा मान लिया गया हो अथवा दिनांक ०१ जनवरी, २००६ के पश्चात् सेवा में नियुक्त हुए हों, के नगर प्रतिकर भत्ता के संबंध में पूर्व में निर्गत आदेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

6- यह आदेश दिनांक ०१ दिसम्बर, २००६ से प्रभावी होने।

भवदीय,

प्रमुख वि०
(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव

संख्या जी-१-९६४(१)/दस-२००६-२०३/९९, तत्पदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव / सचिव, शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० शासन।
- 1- महालेखाकार-१, २ एवं ३, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद / लखनऊ।
- 2- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 3- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-१/२ (तीन-तीन प्रतियों में)
- 4- सचिव, श्री राज्यपाल।
- 5- विधान सभा / परिषद् सचिवालय।
- 6- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 7- समस्त कोषाधिकारी / करिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(मित्त प्रकाश)
विशेष सचिव।

प्रेषक,

बी०एन० दीक्षित,

सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1-शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश।

2-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 11 दिसम्बर, 2008

विषय: स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों, को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिए जाने की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मियों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण हेतु गठित वेतन समिति 2008 के प्रथम प्रतिवेदन की संसत्तुतियों को कतिपय संशोधनों के साथ शासकीय सकल्प संख्या-वे०आ०-2-1313/दस-2008-59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर 2008 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

2- वेतन समिति-2008 के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरूप श्री राज्यपाल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों, विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यू०जी०सी० ए०आई०सी०टी०ई० आई०सी०ए०आर० वेतनमानों से आञ्छादित पदों को छोड़ कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणोत्तर कर्मचारियों, जिन्होंने अपने परिवार को दो बच्चों तक सीमित रखा हो, को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-9(23) (बी) के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमन्य वैयक्तिक वेतन की धनापाशि निम्नानुसार निर्धारित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र० सं०	दिनांक 01-1-96 से प्रभावी वेतनमान	दिनांक 01-1-2008 से लागू वेतन बैंड	सादृश्य ग्रेड-पे	स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमन्य वैयक्तिक वेतन की पुनरीक्षित दरें
1.	2550-55-2660-60-3200	4440-7440	1300.	210
2.	2610-60-3150-65-3540	4440-7440	1400	
3.	2660-65-3300-70-4000	4440-7440	1660	
4.	2750-70-3600-75-4400	5200-20200	1800	
5.	3050-75-3960-80-4590	5200-20200	1900	
6.	3200-85-4900	5200-20200	2000	
7.	4000-100-6000	5200-20200	2400	

अपर पुलिस महादेशक
उ० प्र० पुलिस मुख्यालय
लखनऊ।

16/11/08

8.	4200-100-8150-125-8400	5200-20200	2800	250
9.	4500-125-7000	5200-20200	2800	
10.	4500-125-7250	5200-20200	2800	
11.	5000-150-8000	9300-34800	4200	400
12.	5500-175-9000	9300-34800	4200	
13.	6000-200-10500	9300-34800	4200	
14.	7450-225-11500	9300-34800	4800	450
15.	7500-250-12000	9300-34800	4800	500
16.	8000-275-13500	15600-39100	5400	650
17.	8500-275-14500	15600-39100	5400	
18.	10000-325-15200	15600-39100	6800	
19.	10650-325-15850	15600-39100	6800	750
20.	12000-375-16500	15600-39100	7600	
21.	14300-400-18300	37400-67000	8700	
22.	16400-450-20000	37400-67000	8900	900
23.	18400-500-22400	37400-67000	10000	1000

3- उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 4601/16-11-79-9-153-99 दिनांक 23 फरवरी, 1980 एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। सम्बन्धित शासनादेशों की अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

भवदीय,

 (बी०एन० दीक्षित)
 सचिव

संख्या जी-1-1985(1)/दस-2008-339/2008, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार-1, 2 एवं 3, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
- 2- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 3- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2, (तीन-तीन प्रतियों में)।
- 4- सचिव, श्री राज्यपाल।
- 5- प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय/सचिव, विधान परिषद् सचिवालय।
- 6- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 7- प्रमुख सचिव चिकित्सा अनुभाग-11 को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि यदि उक्त आदेश में कोई संशोधन आपेक्षित हो तो कृपया तत्काल वित्त विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से.

(शिव प्रकाश)
 विशेष सचिव।

प्रेषक,

श्री अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- (1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक : 08 दिसम्बर, 2008.

विषय:-वेतन समिति, उ0प्र0 (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राजकीय कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड/वेतनमान एवं ग्रेड वेतन की स्वीकृति।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिए वेतन समिति का गठन संकल्प संख्या- वे0आ0-2-870/दस- 34(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 29 अगस्त, 2008 सपठित संकल्प संख्या-वे0आ0-2-824/दस-34 (एम)/ 2008 टी0सी0, दिनांक 22 अगस्त, 2008 द्वारा किया गया। उक्त समिति द्वारा अपना प्रथम प्रतिवेदन शासन को 20 नवम्बर, 2008 को प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रतिवेदन की संस्तुतियों को सम्यक् विचारोपरान्त कतिपय संशोधनों के साथ संकल्प संख्या-वे0आ0-2-1313/दस-54(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

2- वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से संलग्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड/वेतनमान एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त संलग्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड/वेतनमान एवं ग्रेड वेतन ऐसे पदधारकों को भी वैयक्तिक रूप से अनुमन्य होगा, जो राज्य सरकार द्वारा अपनायी गयी समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित सेवा अवधि/शर्तों की पूर्ति पर वैयक्तिक रूप से प्रोन्नति के पद का वेतनमान अथवा उच्च वेतनमान दिनांक 01 जनवरी, 2006 अथवा कोई अनुवर्ती तिथि जिससे संशोधित वेतन संरचना को सम्बन्धित द्वारा चुने जाने का विकल्प दिया गया हो, को प्राप्त कर रहे थे।

4- दिनांक 01 जनवरी, 2006 अथवा कोई अनुवर्ती तिथि जिससे संशोधित वेतन संरचना को सम्बन्धित द्वारा चुने जाने का विकल्प दिया गया हो, के उपरान्त समयमान वेतनमान की वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत स्वीकृत/देय कोई लाभ पुनरीक्षित वेतन संरचना में देय नहीं रह जायेगा।

5- ऐसे सर्वग/पदों, जिनके वेतनमान का उच्चीकरण/संशोधन दिनांक 01 जनवरी, 2006 के बाद हुआ है, के पदधारकों को यह विकल्प होगा कि वे या तो दिनांक 01 जनवरी, 2006 को विद्यमान वेतनमान के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अथवा उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन उच्चीकरण/संशोधन के दिनांक से चुन लें।

15/12/08

6- वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों लागू होने के फलस्वरूप पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण, संशोधित दरों पर देय मंहगाई भत्ता, समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 (स्ट्रोनयन.) की संशोधित व्यवस्था, मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, स्वैच्छिक परिवार कल्याण प्रोत्साहन तथा सामूहिक बीमा की संशोधित दरों के सम्बन्ध में आदेश अलग से जारी किये जायेंगे।

7- विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक संस्थाओं के शिक्षक (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों सहित) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणोत्तर कर्मचारियों/अधिकारियों, कार्यप्रभारित कर्मचारियों, स्थानीय निकायों (जिला पंचायत, जल संस्थान एवं विकास प्राधिकरण सहित), स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों/अधिकारियों तथा सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों के कर्मचारियों/ अधिकारियों पर इस शासनादेश द्वारा की जा रही व्यवस्था लागू नहीं होगी।

8- उपर्युक्त पुनरीक्षित वेतन संरचना के लागू होने के फलस्वरूप निर्धारित वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन तथा संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ता के अतिरिक्त अन्य लाभ यथा विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन तथा अन्य भत्ते आदि की धनराशि में (दिनांक 01 जनवरी, 2008 से 30 नवम्बर, 2008 तक की अवधि में) कोई परिवर्तन नहीं होगा। दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से आगे की अवधि में प्रस्तर-6 में उल्लिखित भत्ते एवं सुविधाओं को छोड़कर अन्य भत्तों/सुविधाओं की धनराशि दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को देय धनराशि ही रहेगी।

9- इस शासनादेश द्वारा राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतनमान उपरोक्त प्रस्तरों के अधीन संलग्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित माने जायेंगे और इनके लिए शासन के विभिन्न विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रमुख (२२)
(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव।

संख्या-वे0आ0-2-1314(1)/दस-59(एम)/2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषत :—

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I एवं II तथा (आडिट)- I एवं II, उ0प्र0, इलाहाबाद
- 2- प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।
- 3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
- 4- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 5- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, उत्तर प्रदेश।
- 6- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग।
- 7- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 8- उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 9- इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 10-गार्डबुक।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1314 / दस-59(एम) / 2008,
दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 का संलग्नक।

क्र० सं०	वर्तमान वेतनमान (रु०)	पुनरीक्षित वेतन संरचना		
		वेतन बैंड/ वेतनमान का नाम	सादृश्य वेतन बैंड / वेतनमान (रु०)	सादृश्य ग्रेड वेतन (रु०)
1	2	3	4	5
1	2550-55-2660-60-3200	-1एस	4440-7440	1300
2	2610-60-3150-65-3540	-1एस	4440-7440	1400
3	2650-65-3300-70-4000	-1एस	4440-7440	1650
4	2750-70-3800-75-4400	वेतन बैंड-1	5200-20200	1800
5	3050-75-3950-80-4590	वेतन बैंड-1	5200-20200	1900
6	3200-85-4900	वेतन बैंड-1	5200-20200	2000
7	4000-100-6000	वेतन बैंड-1	5200-20200	2400
8	4500-125-7000	वेतन बैंड-1	5200-20200	2800
9	4500-125-7250	वेतन बैंड-1	5200-20200	2800
10	5000-150-8000	वेतन बैंड-2	9300-34800	4200
11	5500-175-9000	वेतन बैंड-2	9300-34800	4200
12	6500-200-10500	वेतन बैंड-2	9300-34800	4200
13	7450-225-11500	वेतन बैंड-2	9300-34800	4800
14	7500-250-12000	वेतन बैंड-2	9300-34800	4800
15	8000-275-13500*	वेतन बैंड-2	9300-34800	5400
16	8000-275-13500**	वेतन बैंड-3	15600-39100	5400
17	8550-275-14600	वेतन बैंड-3	15600-39100	5400
18	10000-325-15200	वेतन बैंड-3	15600-39100	6600
19	10850-325-15850	वेतन बैंड-3	15600-39100	6600
20	12000-375-16500	वेतन बैंड-3	15600-39100	7800
21	14300-400-18300	वेतन बैंड-4	37400-67000	8700
22	16400-450-20000	वेतन बैंड-4	37400-67000	8900
23	18400-500-22400	वेतन बैंड-4	37400-67000	10000
24	22400-525-24500	वेतन बैंड-4	37400-67000	12000
25	28000 (नियत)	शीर्षस्थ वेतनमान	80000 (नियत)	शून्य

* जहाँ इस वेतनमान के पद शत प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाते हों अथवा जहाँ यह वेतनमान समयमान वेतनमान/ए.सी.पी. के रूप में देय हो।

** जहाँ इस वेतनमान के पदों पर सीधी भर्ती भी हो।

Am

प्रेषक,

श्री अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- (1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- (2) वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- (3) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)/शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद/लखनऊ।
- (4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 08 दिसम्बर, 2008

विषय:- राज्य कर्मचारियों, राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यू0जी0सी0, ए0 आई0 सी0 टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को दिनांक 1-06-2006, 01-07-2006, 01-01-2007, 01-07-2007, 01-01-2008 एवं 01-07-2008 से अनुमन्य महंगाई भत्ते की संशोधित दरें।

पठित निम्नलिखित:-

- (1) शासनादेश संख्या वे0आ0-1-606/दस-2008-42(एम)/97, दिनांक 27 मई, 08
- (2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या-1(3)/2008-ई-II(बी), दिनांक 29-08-2008
- (3) शासकीय संकल्प संख्या-वे0आ0-2-1313/दस-54(एम)/08, दिनांक 08 दिसम्बर, 08
- (4) शासनादेश संख्या वे0आ0-2-1314/दस-59(एम)/08, दिनांक 08 दिसम्बर, 08
- (5) शासनादेश संख्या वे0आ0-2-1315/दस-59(एम)/08, दिनांक 08 दिसम्बर, 08

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को उपर्युक्त कम सं0-(2) पर उल्लिखित कार्यालय-ज्ञापन द्वारा दिनांक 01-01-2006, दिनांक 01-07-2006, 01-01-2007, 01-07-2007, 01-01-2008 एवं 01-07-2008 से निम्नानुसार संशोधित दरों पर महंगाई भत्ते की स्वीकृति के आदेश जारी किये गये हैं:-

तिथि जिस दिन से देय है

प्रतिमाह महंगाई भत्ते की दर

01-01-2006

शून्य

01-07-2006

वेतन का 2 प्रतिशत

01-01-2007

वेतन का 6 प्रतिशत

01-07-2007

वेतन का 9 प्रतिशत

01-01-2008
01-07-2008

वेतन का 12 प्रतिशत
वेतन का 16 प्रतिशत

2- उपर्युक्त क्रम संख्या-3 पर उल्लिखित शासकीय संकल्प, दिनांक 08दिसम्बर, 2008 के क्रम में राज्यपाल महोदय दिनांक 01-01-2006, दिनांक 01-07-2006, 01-01-2007, 01-07-2007, 01-01-2008 एवं 01-07-2008 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में निम्नानुसार संशोधित दरों पर महंगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं:-

तिथि जिस दिन से देय है	प्रतिमाह महंगाई भत्ते की दर
01-01-2006	शून्य
01-07-2006	मूल वेतन का 2 प्रतिशत
01-01-2007	मूल वेतन का 6 प्रतिशत
01-07-2007	मूल वेतन का 9 प्रतिशत
01-01-2008	मूल वेतन का 12 प्रतिशत
01-07-2008	मूल वेतन का 16 प्रतिशत

3- इस आदेश के अनुसार महंगाई भत्ते का उपरोक्त दरों पर भुगतान पूर्व में शासनादेश संख्या वे0आ0-1-656/दस-2006-42(एम)/97, दिनांक 16 जून, 2006, शासनादेश संख्या वे0आ0-1-1415/दस-2006-42(एम)/97, दिनांक 16 नवम्बर, 2006, संख्या वे0आ0-1-702/दस-2007-42(एम)/97, दिनांक 5 जून, 2007, संख्या वे0आ0-1-1514/दस-2007-42(एम)/97, दिनांक 15 अक्टूबर, 2007 एवं सं0-वे0आ0-1-606/दस-2008-42(एम)/97, दिनांक 27 मई, 2008 द्वारा स्वीकृत एवं भुगतान की गई महंगाई भत्ते की धनराशि को समायोजित करने के बाद किया जायेगा।

4- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के आगणन हेतु "मूल वेतन" का तात्पर्य दिनांक 1-1-2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन-संरचना में कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन बैंड में वेतन तथा अनुमन्य ग्रेड वेतन के योग से होगा, किन्तु नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा। परन्तु उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियमों के अंतर्गत वेतन की परिभाषा में आते हों, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नहीं किया जायेगा। परन्तु प्रैक्टिस बन्दी भत्ता को "वेतन" का अंश माना जायेगा अर्थात् प्रैक्टिस बन्दी भत्ता को महंगाई भत्ता के आगणन हेतु सम्मिलित किया जायेगा।

5- महंगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम 9(21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।

6- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता उन कर्मचारियों/शिक्षकों को भी, जो प्रभावी तिथि को सेवारत थे किन्तु इस शासनादेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवारत चाहे जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों से या त्याग-पत्र, सेवा-निवृत्ति, मृत्यु या सेवा-मुक्त होने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गयी हों, सेवा-समाप्ति, सेवा निवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा।

7- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात् 50 पैसे और इससे अधिक को अगले उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

8- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत संशोधित महंगाई भत्ते की दरों के आधार पर दिनांक 1-12-2008 से (दिनांक 01 जनवरी, 2009 को देय) नगद भुगतान किया जायेगा। संशोधित दरों पर भुगतान के फलस्वरूप दिनांक 1-1-2006 से 30-11-2008 तक की अवधि हेतु अवशेष देय का भुगतान शासकीय संकल्प संख्या वे0आ0-2-1313/दस-54(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर-1(13) में प्रावधानित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

भवदीय,

अनूप मिश्र

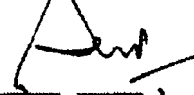
(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव।

संख्या-वे0आ0-1- 1775(1)/दस-42(एम)/2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (01) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 एवं 2 तथा (अडिटर)-1 एवं 2 उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (02) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (03) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (04) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) कमरा नं0-281, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
- (05) प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, लखनऊ।
- (06) प्रमुख सचिव, विधान सभा/परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (07) महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- (08) रीजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर।
- (09) अपर निदेशक, कोषागार शिविर कार्यालय, नवीन कोषागार भवन (प्रथम तल) कचहरी रोड, इलाहाबाद।
- (10) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (11) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (12) निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।
- (13) इरला चेक अनुभाग/इरला चेक (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ)
- (14) सचिवालय के अन्य समस्त अनुभाग।
- (15) गार्ड बुक।

आज्ञा से,


(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।